

## निजी निवेश की कमी

सामान्य अध्ययन – पेपर 3: भारतीय अर्थव्यवस्था और योजना, संसाधन एकत्रीकरण, वृद्धि और विकास से संबंधित मुद्दे।

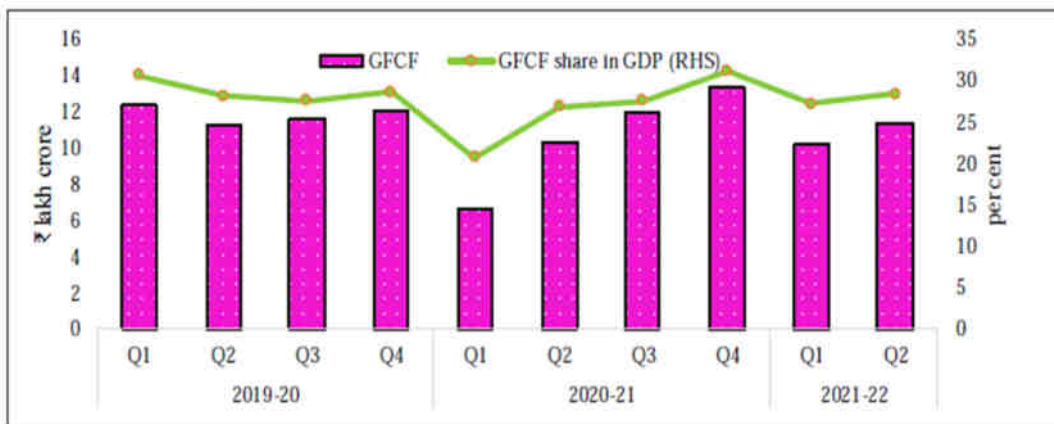
**कीवर्ड :** निजी निवेश, निवेश दर, सकल अचल पूंजी निर्माण, आपूर्ति श्रृंखला की समस्याएं, व्यापार सुधार कार्य योजना, एफडीआई, राष्ट्रीय मुद्राकरण पाइपलाइन, श्रम कानून सुधार, मजदूरी पर कोड, 2019, औद्योगिक भूमि बैंक ।

**चर्चा में क्यों :** सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था उम्मीद से धीमी गति से बढ़ रही थी, इसके बाद, वित्त मंत्री ने निजी क्षेत्र को देश में निवेश बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया।

**संदर्भ:**

- केवल एक दशक से भी कम समय में, भारत का सकल पूंजी निर्माण (निवेश दर) 2010-11 में सकल घरेलू उत्पाद के 40 प्रतिशत के उच्च स्तर से लगभग 10.4 प्रतिशत अंक गिरकर 2021-22 में लगभग 29.6 प्रतिशत हो गया है।
- सकल स्थायी पूंजी निर्माण के हिस्से के साथ, 2015-16 से निवेश गतिविधि मौन रही है , जो अर्थव्यवस्था में निवेश को दर्शाता है, जो सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 29.6 प्रतिशत है।
- महामारी के बाद थोड़ी रिकवरी के बावजूद, 2021-22 के अंत में, निवेश उनके 2019-20 के पूर्व-महामारी के स्तर से केवल 3.7 प्रतिशत अधिक था ।
- औद्योगिक, बुनियादी ढांचे और सेवाओं में नई क्षमताओं को जोड़ने के लिए निवेश प्रस्तावों में 3.57 लाख करोड़ रुपये की वृद्धि हुयी । यह पिछली तीन तिमाहियों में औसत निवेश प्रस्तावों की तुलना में थोड़ी सी अधिक है।
- निजी निवेश कुल मांग का एक महत्वपूर्ण घटक है, जिसने कुल निवेश में 73 प्रतिशत से अधिक का योगदान दिया और 2017-2020 की अवधि के दौरान सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 22 प्रतिशत था। इसके लिए कमजोर कारोबारी धारणा को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है ।

Figure 19: Gross Fixed Capital Formation (GFCF)



Source: NSO, MoSPI

सकल अचल पूंजी निर्माण (जीएफसीएफ), जिसे " निवेश " भी कहा जाता है, को उत्पादित परिसंपत्तियों (दूसरे हाथ की संपत्ति की खरीद सहित) के अधिग्रहण के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसमें उत्पादकों द्वारा अपने स्वयं के उपयोग के लिए ऐसी संपत्ति का उत्पादन, ऋण निपटान शामिल है। यानी यह देश में निवेश के स्तर का सूचक है।

#### कम निजी निवेश के कारण:

- निवेश में गिरावट के कई कारण हैं-
  - आपूर्ति श्रृंखला की समस्या,
  - भूमि अधिग्रहण की समस्या,
  - पर्यावरण और अन्य मंजूरी का अभाव,
  - प्रमोटर हितों की कमी,
  - सख्त श्रम कानून
  - दूसरों के बीच अन्य नियामक बोझ।
- अतीत में, दोहरी बैलेंस शीट समस्या ( एक बैंक जो कॉर्पोरेट सेक्टर के खराब ऋणों से परेशान थे) के बारे में माना जाता था कि वे निवेश गतिविधि को रोक रहे थे। तब से कॉर्पोरेट और बैंक बैलेंस शीट में सुधार हुआ है, लेकिन अर्थव्यवस्था के बड़े हिस्से में संघर्ष जारी है।
- महामारी के दौरान ईसीएलजीएस सुविधा के तहत एमएसएमई द्वारा लिए गए ऋण का 16.4 प्रतिशत खराब हो गया है क्योंकि उधारकर्ता वित्तीय संकट के कारण ऋण का भुगतान करने में सक्षम नहीं हैं।
- अनौपचारिक इकाइयों में, वित्त के औपचारिक स्रोतों तक पहुंच नहीं होने के कारण (जिसके माध्यम से सरकारी सहायता उपलब्ध कराई गई थी ) तनाव और भी गंभीर होने की संभावना है।
- सरकारी उधारी के साथ एक और समस्या यह है कि यह निजी उधारी और निवेश के लिए कोई जगह नहीं छोड़ती है।

#### बढ़ावा देने के लिए सरकार की पहल 'निजी निवेश' :

- व्यापार सुधार कार्य योजना :
  - उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) ने व्यापार सुधार कार्य योजना नामक एक गतिशील सुधार अभ्यास शुरू किया है , जो निर्दिष्ट सुधार मानकों के कार्यान्वयन के आधार पर देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को रैंक करता है।
  - सुधारों ने मौजूदा नियमों और प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और अनावश्यक आवश्यकताओं और कदमों से छुटकारा पाने पर ध्यान केंद्रित किया है।
- एफडीआई में सुधार :
  - सरकार ने एफडीआई को प्रोत्साहित करने के लिए एक निवेशक-अनुकूल रणनीति लागू की है , और अधिकांश क्षेत्र स्वचालित मार्ग के तहत 100% एफडीआई के लिए सुलभ हैं।
  - भारत को निवेशकों के लिए एक वांछनीय और स्वागत योग्य स्थान बनाए रखने के लिए, एफडीआई नीति को भी बार-बार संशोधित किया जाता है। शीर्ष उद्योग मंडलों, संघों, उद्योगों/समूहों के प्रतिनिधियों और अन्य संगठनों सहित हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श के बाद नीति में कोई भी बदलाव किया जाता है।
- राष्ट्रीय मौद्रीकरण पाइपलाइन परियोजना :

- इन्फ्रास्ट्रक्चर में उपलब्ध निवेश के रास्ते के निवेशकों और डेवलपर्स को एक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय मौद्रीकरण पाइपलाइन (एनएमपी) को 2021 में लॉन्च किया गया था।
- चार साल की अवधि में, केंद्र सरकार की मूल संपत्ति के लिए एनएमपी का कुल सांकेतिक मूल्य 6 लाख करोड़ (US\$ 75.18 बिलियन) रुपये आंका गया है।।
- **श्रम कानूनों में सुधार:**
  - श्रम और रोजगार मंत्रालय ने व्यापार को आसान बनाने के लिए श्रम कानूनों को कारगर बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं।
  - 29 केंद्रीय श्रम कानूनों के प्रासंगिक प्रावधानों को संघनित, संयोजित और युक्तिसंगत बनाकर, सरकार ने चार श्रम संहिताओं को अधिसूचित किया है:
    - मजदूरी पर कोड, 2019
    - औद्योगिक संबंध संहिता, 2020
    - सामाजिक सुरक्षा पर संहिता, 2020
    - व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और काम करने की स्थिति पर कोड, 2020।
- **रियायती कर की दर:**
  - नई घरेलू कंपनियों को भारत में अपनी विनिर्माण इकाइयाँ स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए, सरकार ने 15% की रियायती कर दर को बढ़ाकर 31 मार्च, 2024 कर दिया है।
- **औद्योगिक भूमि बैंक:**
  - सरकार ने इंडिया इंडस्ट्रियल लैंड बैंक (IILB) की शुरुआत की, जो एक जीआईएस - आधारित पोर्टल है – जिसमें औद्योगिक बुनियादी ढाँचे से संबंधित सूचनाओं का एक-स्टॉप रिपॉजिटरी - कनेक्टिविटी, इन्फ्रास्ट्रक्चर, प्राकृतिक संसाधन, इलाके, खाली प्लॉट पर प्लॉट-स्तरीय जानकारी, गतिविधि की रेखा, और संपर्क विवरण शामिल है।
- **सिंगल विंडो सिस्टम:**
  - सितंबर 2021 में, वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली (NSWS) का शुभारंभ किया। सिंगल विंडो पोर्टल अनुमोदन और मंजूरी के लिए निवेशकों के लिए ऑन-ई-स्टॉप शॉप बन जाएगा, जो पारिस्थितिकी तंत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही लाएगा।

### आगे की राह :

- यह सच है कि निजी क्षेत्र निवेश के लिए लाभ कमाने के लिए व्यावसायिक निर्णय लेता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि पूंजीगत वस्तुओं में एक लंबा गर्भकाल होता है। निवेश के फैसले गंभीर रूप से निर्भर करते हैं-
  - नए निवेश द्वारा उत्पादित उत्पादन का स्तर,
  - कराधान प्रणाली,
  - कम ब्याज दर व्यवस्था में परिलक्षित ऋण की लागत,
  - क्रेडिट की समय पर डिलीवरी और
  - घरेलू और वैश्विक अर्थव्यवस्था की व्यावसायिक उम्मीदें।
- इस प्रकार, निवेश को बढ़ावा देने के लिए सकारात्मक भावनाओं की आवश्यकता होती है जिसे " गणितीय अपेक्षा के बजाय सहज आशावाद" द्वारा निर्देशित किया जाना चाहिए।

- भारत वर्तमान में वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ियों में से एक के रूप में जाना जाता है। देश तेजी से आर्थिक तरक्की कर रहा है और 2025 तक भारत के 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की उम्मीद है।
- भारत के लिए उच्च विकास पथ पर बने रहने के लिए अर्थव्यवस्था में निजी निवेश को बढ़ाना समय की मांग है।

स्रोत: <https://indianexpress.com/article/opinion/editorials/centre-has-been-pushing-for-investments-but-private-sector-seems-hesitant-to-take-the-plunge-8151622/>

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

Q. भारत में निवेश के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये।

1. पिछले दशक में भारत का सकल पूंजी निर्माण (निवेश दर) गिर गया है।
2. निजी निवेश समग्र मांग का एक महत्वपूर्ण घटक है जिसने कुल निवेश में 73 प्रतिशत से अधिक का योगदान दिया है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) दोनों 1 और 2
- d) इनमें से कोई नहीं

उत्तर : C

व्याख्या :

- केवल एक दशक से भी कम समय में, भारत का सकल पूंजी निर्माण (निवेश दर) 2010-11 में सकल घरेलू उत्पाद के 40 प्रतिशत के उच्च स्तर से लगभग 10.4 प्रतिशत अंक गिरकर 2021-22 में लगभग 29.6 प्रतिशत हो गया है।
- निजी निवेश कुल मांग का एक महत्वपूर्ण घटक है, जिसने कुल निवेश में 73 प्रतिशत से अधिक का योगदान दिया और 2017-2020 की अवधि के दौरान सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 22 प्रतिशत था। इसके लिए कमजोर कारोबारी धारणा को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न \_ "भारत के लिए 2025 तक 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के लिए अर्थव्यवस्था में निजी निवेश महत्वपूर्ण है।" कथन का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए।